

# विमान सेवा के लिए नहीं मिला एनओसी

**छत्तीसगढ़ संवाददाता**  
बिलासपुर, 11 मार्च | डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने घरेलू विमान सेवा के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया है। इसका कारण चक्रभाटा हवाई पट्टी में पर्याप्त सुविधा नहीं होने को बताया गया है। नागरिक विमानन सचिव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं।

एयर छत्तीसगढ़ के नाम से राज्य में निजी घरेलू विमान सेवा प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों को जोड़ेगी। सरकार ने छत्तीसगढ़ एविएशन अकादमी भिलाई को यह सेवा शुरू करने की अनुमति दी है। इसके लिए डीजीसीए की आठ सदस्यीय टीम ने कैप्टन सिद्धार्थ शुक्ला के नेतृत्व में बीते जनवरी में चक्रभाटा हवाई अड्डे का निरीक्षण किया था। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधा सहित अन्य मापदंडों को लेकर चले रहे कार्यों के बारे में अफसरों से जानकारी ली थी। इस दौरान प्रशासन ने उन्हें हवाई पट्टी के 6 किलोमीटर के क्षेत्र में जानवरों का प्रवेश रोकने के लिए बाधाएं बनाने की बात कही थी।

इसके बाद भी निरीक्षण के दौरान डीजीसीए के अफसर चक्रभाटा हवाई पट्टी में जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं दिखे। यही कारण है कि घरेलू विमान सेवा के लिए डीजीसीए

**नहीं बना एंटी हाइजेकिंग प्लान**



ने एनओसी जारी नहीं की है। इसे ध्यान में रखते हुए नागरिक विमानन विभाग के सचिव आरएस विश्वकर्मा ने कलेक्टर सोनमणी बोर को पत्र लिखा है। इसमें लैडिज टॉयलेट, यात्रियों के आने-जाने की व्यवस्था,

हवाई पट्टी को सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जात हो कि निरीक्षण के दौरान डीजीसीए के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के अफसरों से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के बारे में पूछा था। यही नहीं हवाई पट्टी पर सुरक्षा बल के नहीं होने पर असंतोष जाहिर किया गया था। इस पर जिला प्रशासन के अफसरों ने उन्हें बस्तर, राजनांदगांव में नक्सलियों का खतरा होने की जानकारी दी।

चक्रभाटा हवाई पट्टी के निरीक्षण पर पहुंचे अफसरों ने हाइजेकिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि एंटी हाइजेकिंग की योजना को गंभीरता से लेना चाहिए। जिला प्रशासन के अफसरों ने उन्हें शीघ्र ही पुलिस अफसरों के साथ बैठक करने की जानकारी दी थी, लेकिन अभी तक एंटी हाइजेकिंग प्लान नहीं बन सका है। इस बारे में अपर कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया कि चक्रभाटा एयरस्ट्रीप पर सुविधाएं जुटाने के निर्देश मिले हैं। बिल्हा एसडीएम को इसकी जवाबदारी सौंपी गई है।



पिथौरा बस स्टैंड के भीड़भाड़ वाले इलाके में ट्रकों आती जाती हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। छाया छत्तीसगढ़

## प्रसूता से वसूली नर्स निलंबित

**डीन ने जारी किया आदेश**

**छत्तीसगढ़ संवाददाता**  
बिलासपुर, 11 मार्च | सिम्स में प्रसूता से रूपए वसूली करने वाली नर्स को गॉयनिक विभाग से हटाने के बाद बुधवार को निलंबित कर दिया गया है। मरीजों व उनके परिजनों से वसूली करने के मामले में यह पहली कार्रवाई है।

सिम्स में पिछले दिनों एक प्रसूता के परिजनों से रकम की वसूली की गई थी। इसे लेकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचा था। इसके बाद आनन-फानन में अस्पताल अधीक्षक प्रो. आर मूर्ति ने जांच कमेटी का गठन कर दिया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद पिछले दिनों वसूली करने वाली नर्स को गॉयनिक विभाग से हटा दिया गया। कार्रवाई के लिए डीन के लौटने का इंतजार किया जा रहा था। बुधवार को डीन प्रो. बीएल पटेल ने रायपुर से लौटते ही प्रसूता के परिजनों से वसूली करने वाली नर्स को निलंबित कर दिया। मरीजों के परिजनों से वसूली किए जाने के मामले में यह पहली कार्रवाई है। डीन प्रो. पटेल ने बताया कि मरीजों से वसूली के मामले में दौषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। वसूली मामले में जांच के लिए डॉ. डीआर पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

## नकल कराने वाले 7 ग्रामीणों को जेल अपर कलेक्टर और एसडीएम ने की कार्रवाई

**छत्तीसगढ़ संवाददाता**  
बिलासपुर, 11 मार्च | मस्तूरी ब्लॉक के लोहर्सी व बोहारडीह परीक्षा केंद्र में नकल सामग्री पहुंचाने वाले सात लोगों को हवालात में बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही बुधवार को हुई 10 वीं की परीक्षा में आठ नकलचियों के खिलाफ नकल प्रकरण बनाया गया है।

शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के हस्तक्षेप पर अब पुलिस ने भी नकल कराने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिरिक्त कलेक्टर टीके वर्मा और एसडीएम संतोष देवानं की टीम ने बुधवार की सुबह मस्तूरी क्षेत्र के बदनाम परीक्षा केंद्रों में दबिश दी। उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी। परीक्षा केंद्र के बाहर नकल सामग्री देने वालों का हुजूम लगा हुआ था। अधिकारियों के पहुंचने के बाद भी भीड़ मौके से हटने को तैयार नहीं थी। इस पर पुलिस के जवानों ने उन्हें दौड़ाना शुरू किया। अधिकांश तो मौके से भाग गए, लेकिन बोहारडीह और सोन लोहर्सी परीक्षा केंद्र में सात लोगों को

पकड़ने में पुलिस सफल रही। सभी को प्रतिबंधात्मक धारा के तहत हवालात में डाल दिया गया है। इनमें ग्राम बगबुडुवा निवासी क्रांति कुमार पिता हितेंद्र साहू, भुवकुंडा निवासी अनिल कुमार पिता धुरीराम, सुकुलकारी निवासी बीरबल

**आठ नकलची भी पकड़े गए**

पिता मनहरण, जनी सोनी पिता जगन्नाथ, खपरी निवासी गणेशराम कुंठे, गाड़ाडीह के धीरेंद्र दिनकर, मुरलीडीह के लाला राधे शामिल हैं। पहली बार हुई पुलिस कार्रवाई से नकल कराने वालों में हड़कंप मच गया है। इधर, बदनाम परीक्षा केंद्रों में उड़नदस्ते की टीम भी बैठ गई थी। ओखर में तो दसवों की परीक्षा में एक साथ तीन टीमों के सदस्य मौजूद थे। इसके अलावा सभी जाह अधिकारियों का दल परीक्षा होते तक केंद्र में ही मौजूद था। इससे नकलचियों को काफ़ी परेशानी

हुई। इधर परीक्षा केंद्र टिकारी में बैठक व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले दो पर्यवेक्षकों को नोटिस दिया गया है। उड़नदस्ते की टीम जब वहां पहुंची, तो पता चला कि दो कमरों में बैठक व्यवस्था में गड़बड़ी करते हुए एक ही सेट वाले परीक्षार्थियों को आसपास बैठा दिया गया था। इसकी जानकारी मिलते ही उड़नदस्ते ने पर्यवेक्षकों को नोटिस जारी कर बैठक व्यवस्था को दुरुस्त किया।

**सलवार सूट में लिखा नकल**

टिकारी में एक लड़की अपने कपड़े में नकल लिखकर आई थी। जांच में उड़नदस्ते की नजर उस पर पड़ गई। नकल प्रकरण बनाने के लिए उस लड़की के कपड़े के एक छोर अधिकारी काटकर ले गए। इस साल पहली बार किसी छात्र द्वारा कपड़े में नकल लिखकर लाने की घटना हुई है।

## भाजपा में युवाओं को मिला अवसर

मगरलोड, 11 मार्च | भाजपा के स्थानीय समिति चुनाव में युवाओं को नेतृत्व का अवसर दिया गया है।

केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर चुनाव अधिकारी श्रीमती राखी साहू, वरिष्ठ भाजपा नेत्री संरंपर खिसोर के नेतृत्व में बूथ क्रमांक 54, 55, 56 और 57 में सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। जिसमें बूथ क्रमांक 54 से ओंकार सिन्हा अध्यक्ष, मंगेशराम साहू उपाध्यक्ष आशीष मांडो महामंत्री एवं राजकुमार सिन्हा सचिव, बूथ 55 के लिए मुकेश साहू अध्यक्ष, तुलाराम टंडन उपाध्यक्ष, जयंत राय महामंत्री, निर्मल साहू सचिव, बूथ 56 में बहुराम साहू अध्यक्ष, उपाध्यक्ष केशव राम साहू, महामंत्री विकास कोसरीया, सचिव युवराज, बूथ 57 में अध्यक्ष केशव राम साहू, उपाध्यक्ष आसकुमार साहू, महामंत्री हेमप्रकाश व सचिव हीरामन साहू को चुना गया। यह चुनाव पार्षद भवानी यादव, घनश्याम, ओपी चंद्रवंशी, नरेश अग्रवाल, मीना बाई कोसले झमित सिन्हा, रामविशाल, डोमार ध्रुव, मुरली धर जगत, नारायण साहू आदि की मौजूदगी में संपन्न हुआ।

## मंडल ने 121 घरों में किया अंधेरा

**बिजली बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटा**

**छत्तीसगढ़ संवाददाता**  
बिलासपुर, 11 मार्च | बकाया वसूली के लिए बुधवार को चलाए गए अभियान के दौरान मंडल ने बिजली काटने की संचुरी बनाई। इस दौरान बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले 121 लोगों के कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिए गए। 11 करोड़ की वसूली के लिए सिटी सर्किल के पूर्वी व पश्चिमी जोन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 22 लाख रूपए की वसूली के लिए 150 बकाएदारों से संपर्क किया गया। मौके पर बिजली बिल की राशि जमा नहीं करने वाले 100 लोगों की बिजली काट दी गई। मंडल को इनसे 9 लाख रूपए लेने हैं।

अभियान के दौरान 50 लोगों से 10 लाख रूपए की वसूली करने में दल को सफलता मिली। पूर्वी जोन द्वारा 20 लाख रूपए की वसूली के लिए 12 मार्च को विद्यानगर स्थित शिवमंदिर में शिविर लगाया जाएगा। मंडल को इनसे 2 लाख 15 हजार

## केमिस्ट प्रशिक्षण कार्यशाला 14 को

थानखम्हरिया, 11 मार्च | दुर्गदवा विक्रेता संघ द्वारा दवा व्यवसाय में होने वाले परिवर्तन एवं परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर एक केमिस्ट प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 14 मार्च को कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई में रखा गया है। जिसमें पूरे जिले के केमिस्ट बंधु भाग लेंगे। कार्यशाला का शुभारंभ केबिनेट मंत्री हेमचंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस. शिन्डे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री एआईओसीडी गौतमचंद्र धोंग, अध्यक्ष छ.ग. दवा विक्रेता संघ सुभाष अग्रवाल के विशिष्ट आतिथ्य के साथ महासचिव छग दवा विक्रेता संघ अविनाश अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न होगा।

## धान के बोरे में कंकर-पत्थर, कार्रवाई शुरू

नवापारा राजिम, 11 मार्च | जौदा भाटा धान संग्रहण केंद्र में जब किए गए कंकर-गिट्टी युक्त धान के सिलसिले में एडिशनल एसपी ने जांच शुरू कर दी है। मानिकचौरी और बासिन सोसायटी से आए घटिया किसम के धान का पंचनामा खाद्य अधिकारी दिनेश पशोने ने बनाकर पुलिस को सौंपा था। इसके बाद एडिशनल एसपी लाल उम्मेद सिंह रायपुर से यहां जांच के लिए पहुंचे।

अधिकारियों ने इस धान के बोरे एवं परिवहन करने वाले ट्रक को भी तौल करकर निशान लगाया और उसे जब्त कर वहीं पर डिपो प्रभारी को उसकी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया। इस



प्रकरण में हजारों बोरे धान की अफरा-तफरी का अंदेश जाता जा रहा है। मिलावटी धान पकड़ने के बाद से ट्रक चालक फरार हैं। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

## पटवारी को रिश्वत नहीं दी तो मुआवजे में की गड़बड़ी

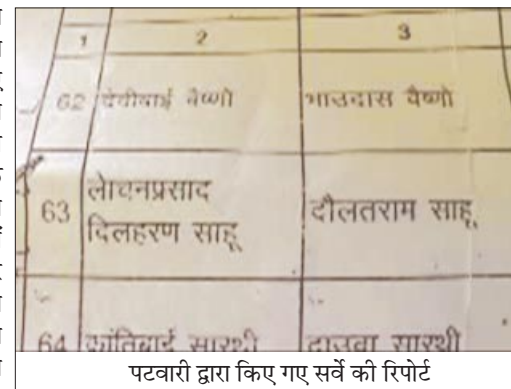
**भरे-पूरे मकान को बता दिया बिना छत का**

**छत्तीसगढ़ संवाददाता**  
जांजगीर-चांपा, 11 मार्च | मड़वा-तेंदूभाटा में निर्माणाधीन सरकारी उपक्रम छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों में मुआवजा प्रकरण बनाने के लिए किए गए सर्वे में पटवारी ने जमकर मनमानी की है।

जिन लोगों ने पटवारी की जब नहीं भरी या उसके कहे अनुसार नहीं किया, उनके साथ मुआवजे के सर्वे में खेल किया गया और जिन्होंने उसकी मुट्टी गरम की, उसके लिए फर्जी प्रकरण भी बना दिए। सरकारी पावर प्लान्ट में हुए मुआवजे के खेल के कुछ कागजात छत्तीसगढ़ को मिले हैं। संवाददाता ने मौके पाकर जाकर इसकी पड़ताल की तो पटवारी द्वारा किए गए इस खेल का पता चला है। अधिकारियों से भी इस मामले की शिकायत हुई है, जिसमें उन्होंने माना है कि कुछ ग्रामीणों के साथ अन्याय हुआ है।

बलौदा विकासखंड के ग्राम मड़वा तेंदूभाटा में लगाए जा रहे 5-5 सौ मेगावाट के दो विद्युत संयंत्रों के लिए तेंदूभाटा के 103 परिवारों की जमीनों अधिग्रहित की गई है और पटवारी सर्वे के आधार पर मुआवजा प्रकरण बनाए गए हैं। पावर प्लान्ट के लिए अधिग्रहित किए जा रहे जमीनों मकानों में से एक मकान दौलतराम साहू का है जो अपने परिवार के साथ यहां रहते हैं। जिस जमीन पर मकान बनाया है,

शासन से उसका पट्टा भी मिला हुआ है। 10 मार्च को यहां पुनर्वास और मजदूरी भुगतान के लिए हुए हंगामे के दौरान गांव पहुंचे इस संवाददाता को दौलतराम ने अपनी दास्तान सुनाई, उसने बताया कि जमीन अधिग्रहण के कुछ साल पहले पटवारी ने हमारी जमीन में से कुछ हिस्से की मांग की थी, इंकार किए जाने पर पटवारी के. के. श्याम नाराज हो गया था, उसके बाद जब पावर प्लान्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मौका आया तो उसने पचास हजार रूपए रिश्वत मांगी, रूपए नहीं दिए जाने पर गलत सर्वे करके कम मुआवजा बना दिया, जबकि हमारे मकान से छोटे छप्परयुक्त



पटवारी द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट

रिपोर्ट देकर किस तरह मुआवजा प्रकरणों में खेल किया है। इसके अलावा और भी कुछ मामले पटवारी के खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आते रहे हैं, जिसमें पटवारी श्री श्याम पर गंभीर अनियमितता के बावजूद अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। चार-पांच माह पूर्व तत्कालीन अपर कलेक्टर सुकुमार चंद ने भी मुआवजे में गड़बड़ी का एक मामला सामने आने के बाद उक्त पटवारी को जमकर फटकार लगाई थी और बिना कार्रवाई किए छोड़ दिया था। कार्रवाई न होने से पटवारी के हांसले बुलंद होते रहे और उसने मुआवजे के इस खेल में लाखों रूपए बटोरे। अगर पटवारी द्वारा किए गए सर्वे की सही सही जांच की जाए तो कई मामले सामने आ सकते हैं। दौलतराम ने जांजगीर एसडीएम एस. सी. श्रीवास्तव, पावर जनरेशन कंपनी के एसई आर. पी. निगम से मामले की लिखित शिकायत की है और उसके मकान का सही मुआवजा दिलाने की मांग की है।

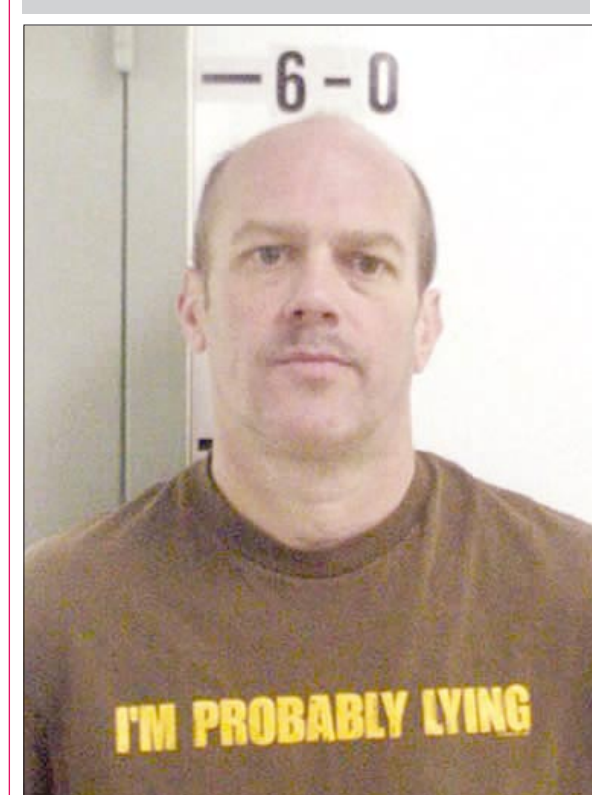
मकानों का ज्यादा मुआवजा बना दिया। दौलतराम की बातें उसके पास रखे दस्तावेजों से भी प्रमाणित होती हैं, जिसमें सर्वे की गई जमीन के बारे में लिखा गया है कि कच्ची मिट्टी की दीवार, छत नहीं है।

छत्तीसगढ़ द्वारा खींची गई तस्वीर से इस बात का सहज ही अंदाजा लग जाता है कि पटवारी ने झूठी

## शिकायत मिली है - श्रीवास्तव

इस मामले में जांजगीर के एसडीएम एस. सी. श्रीवास्तव का कहना है कि मामले की शिकायत मिली है, दौलतराम के मकान का पूरक प्रकरण बनाकर सही मुआवजा दिया जाएगा, पटवारी के विरुद्ध पैसे मांगे जाने की शिकायत नहीं मिली है, फिर भी हम पता करेंगे। वहां छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के एसई आर. पी. निगम ने कहा कि मामले की शिकायत हमें भी मिली है, वास्तव में ग्रामीण के साथ अन्याय हुआ है, पटवारी द्वारा पचास हजार बात का सहज ही अंदाजा लग जाता है कि पटवारी ने झूठी

## सैलानी की डायरी



दुनिया के कई देशों में पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है तो उसकी कुछ तस्वीरें लेकर रिकॉर्ड में रखी जाती हैं ताकि बाद में किसी दूसरे मामले में शिनाख्त के काम आए। ऐसे में कुछ लोग ऐसे मजदार कपड़ों में पकड़ाए रहते हैं कि उनकी तस्वीरें कार्टून की तरह हो जाती हैं। जैसे इस गिरफ्तार व्यक्ति की टी-शर्ट पर लिखा हुआ है - 'मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ।'

पाठक इस कॉलम के लिए टुनिया भर की तस्वीरें भेज सकते हैं। अगर तस्वीर उनकी खींची हुई हो तो उसका जिक्र करें।  
p.n.chhattisgarh@gmail.com

## रोजगार गारंटी की रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी

**छत्तीसगढ़ संवाददाता**  
बिलासपुर, 11 मार्च | केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का एमआईएस डायट को मान्य करने का आदेश दिया है। इसके तहत इस दिन से कोई भी एजेंसी जिला पंचायत कार्यालय को प्रगति रिपोर्ट नहीं देगी।

मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल से कोई भी एजेंसी जिला पंचायत कार्यालय को प्रगति रिपोर्ट नहीं देगी। उनके द्वारा एमआईएस में फीड किया गया डायट ही मान्य होगा। इस संबंध में सीईओ श्री बंसल ने सभी एजेंसियों के अफसरों को दिशा-निर्देश दिया है और कहा कि मार्च तक कि पेंडिंग एंटी पूरी कर ली जाए, ताकि बाद में परेशानी न हो। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का एमआईएस डायट को मान्य करने का आदेश दिया है। इससे एजेंसियों को बार-बार जिला पंचायत का चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा। इसके साथ ही एजेंसियों की दी गई जानकारी कितनी सही है,

इसका पता कोई भी कभी भी एमआईएस डायट को देखकर लगा लेगा।

जिला पंचायत सीईओ मुकेश बंसल ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में निर्माण एजेंसियों को समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के आंकड़ों में जायजा लिया। उपसंचालक उद्यानिकी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े देखकर वे भड़क गए। उन्होंने दो ट्रक शब्दों में कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही नहीं है। आभी-अधूरी जानकारी पेश करने के बाद वे किस अधिकार से कंटीजेंसी की राशि मांग रहे हैं।

## किसानों की बैठक कल

बालोद, 11 मार्च | गंगा मैया प्रांगण झलमला में किसानों की जरूरी बैठक 12 मार्च को सुबह 10 बजे रखी गई है। जिसमें किसान संघ के अध्यक्ष दाऊ नेमसिंह साहू विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में चर्चा होगी।



दौलतराम साहू अपने परिवार के साथ